नैनीताल में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध। 2022 का आवेदन संख्या 370

प्रवीण धामा उर्फ डम्पी ..... याचिकाकर्ता

बनाम।

उत्तराखण्ड राज्य और अन्य.....प्रतिवादी

उपस्थित: श्री विकास आनंद, याचिकाकर्ता के वकील।
श्री ललित मिगलानी, राज्य के लिए आगा/प्रतिवादी नंबर 1।
श्री ललित शर्मा, प्रतिवादी संख्या 2 और 3 के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय रवीन्द्र मैठानी, जे. (मौखिक) वर्तमान याचिका में चुनौती प्रथम अपर न्यायालय द्वारा 2018 के सत्र परीक्षण संख्या 12, राज्य बनाम विनीत एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.09.2021 को दी जाती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर (संक्षेप में, "मामला")। आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, याचिकाकर्ता द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, "संहिता") की धारा 311 के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. विवाद की सराहना करने के लिए आवश्यक तथ्य, संक्षेप में यहां दिए गए हैं। याचिकाकर्ता और दो अन्य के खिलाफ निजी प्रतिवादियों ("मुखबिरों") द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी , जिसके अनुसार, 29.09.2017 को याचिकाकर्ता और सह-आरोपी ने बिट्टू चौधरी की हत्या कर दी थी। इस मामले में जांच के बाद याचिकाकर्ता को छोड़कर चार लोगों के खिलाफ चार्जशीट पेश किया गया था. मुकदमा चला। शुरू में दो गवाह पीडब्ल्यू 1 राकेश कुमार और पीडब्ल्यू 2 संजीव पाल सिंह, दोनों मुखबिरों की जांच की गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से धारा 319 के तहत अर्जी दाखिल की गई थी।

3. दिनांक 05.01.2019 के एक आदेश द्वारा, संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन को स्वीकार किया गया था और याचिकाकर्ता को भी मौजूदा अभियुक्तों के साथ मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था। इस मामले में पारित इस आदेश दिनांक 05.01.2019 को याचिकाकर्ता द्वारा इस न्यायालय के समक्ष और माननीय सर्वोच्च न्यायालय (इस न्यायालय में, यह 2019 की आपराधिक संशोधन संख्या 137 थी) के समक्ष असफल रूप से चुनौती दी गई थी और माननीय के समक्ष चुनौती दी गई थी। ble सुप्रीम कोर्ट ने SLP क्रिमिनल नंबर 9947 ऑफ 2019 में)। ऐसा प्रतीत होता है कि संहिता की धारा 319 के तहत याचिकाकर्ता को समन करने के बाद अदालत ने PW1 राकेश कुमार से जिरह करने का अवसर बंद कर दिया था, लेकिन बाद में, याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक आवेदन पर, PW1 राकेश कुमार द्वारा जिरह की गई थी याचिकाकर्ता। PW2 संजीव पाल सिंह से भी जिरह की गई। यह उस स्तर पर है, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा संहिता की धारा 311 के तहत एक आवेदन दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि PW2 संजीव पाल सिंह की जांच के दौरान दिए गए उनके पिछले बयानों के संबंध में जिरह नहीं की जा सकती है। यह वह आवेदन है, जिसे आक्षेपित आदेश द्वारा अस्वीकृत किया गया है।

4. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 145 (संक्षिप्त रूप में, " साक्ष्य अधिनियम " के संदर्भ में पीडब्लू2 संजीव पाल सिंह की आगे की जिरह के लिए शुरू में लिया गया आधार गवाह से उसके पिछले बयानों के संबंध में जिरह नहीं करना है। ")। वास्तव में, PW2 संजीव पाल सिंह की याचिकाकर्ता द्वारा 12.03.2020 को जिरह की गई थी। उस तारीख को उनका मुख्य परीक्षा भी दर्ज किया गया था, जिसमें उनकी पिछली परीक्षा मुख्य परीक्षा 31.10.2018 को पढ़ी गई थी, जिसकी उन्होंने पुष्टि की और PW2 संजीव पाल सिंह ने तब कहा कि उन्होंने 31.10 को जो कुछ भी कहा था .2018, उनका बयान है। वह जोड़ना नहीं चाहता ओर कुछ अधिक। इस मुख्य परीक्षा के आधार पर, PW2 संजीव पाल सिंह की जिरह दर्ज की गई थी। 20.04.2022 को, इस न्यायालय ने निम्नानुसार दर्ज किया: -

".....जब पीडब्लू 2, संजीव पाल को फिर से याचिकाकर्ता द्वारा जिरह के लिए पेश किया गया था, तो उसे पहले दर्ज की गई उसकी मुख्य परीक्षा के बारे में पढ़ा गया था, जिसे उसने सत्यापित किया और उसे परीक्षा-इन के रूप में लिया गया। -अध्यक्ष।

सवाल यह है कि कैसे, किस प्रक्रिया के तहत, इस तरह की मुख्य परीक्षा दर्ज की जा सकती है, जैसा कि PW2 संजीव पाल सिंह का बयान 12.03.2020 को दर्ज किया गया था।"

6. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि जिस तरह से 12.03.2020 को PW2 संजीव पाल सिंह के मुख्य परीक्षा को दर्ज किया गया था, वह साक्ष्य अधिनियम के तहत स्थापित किसी भी प्रक्रिया के अनुसार नहीं है । उनके अनुसार मुख्य परीक्षा संहिता की धारा 273 के मद्देनजर आरोपी की उपस्थिति में दर्ज की जानी है।

7. यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे मामलों में जहां एक अभियुक्त को संहिता की धारा 319 के तहत सम्मन किया जाता है, पहले से ही पेश किए गए गवाहों को फिर से सुना जाना चाहिए। संहिता की धारा 319 उप-धारा (4) का संदर्भ दिया गया है ।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आत्मा राम और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 523 के मामले में फैसले का भी उल्लेख किया है ।

9. आत्मा राम (उपरोक्त) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि, "न्यायालय के समक्ष गवाही देने वाले अभियोजन पक्ष के गवाहों को देखने का अभियुक्त का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है और इस तरह के अधिकार का उल्लंघन गंभीर पूर्वाग्रहपूर्ण है। "

10. दूसरी ओर, निजी उत्तरदाताओं के विद्वान वकील यह प्रस्तुत करेंगे कि 12.03.2020 को, जब PW2 संजीव पाल सिंह अपनी परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, तो उन्हें 31.10.2018 को दर्ज उनकी मुख्य परीक्षा में पढ़ा गया। इस गवाह ने अपने बयान की पुष्टि की और यह भी कहा कि उसके पास इससे ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है जो वह पहले ही कह चुका है। निजी उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि यह एक गवाह के मुख्य परीक्षा की आवश्यकता को पूरा करता है। यह भी तर्क दिया गया है कि उसके बाद, PW2 संजीव पाल सिंह की याचिकाकर्ता द्वारा जिरह की गई है, यह वकील के वकील के अनुसार है निजी उत्तरदाताओं, का अर्थ है कि याचिकाकर्ता ने 31.10.2018 को अपने मुख्य परीक्षा में दर्ज PW2 संजीव पाल सिंह के बयान को अपने मुख्य परीक्षा के रूप में स्वीकार किया है। इसलिए, इस मामले में कोई अनियमितता नहीं की गई है और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. अधिवक्ता के परिवर्तन के आधार पर आगे की परीक्षा के संबंध में यह तर्क दिया जाता है कि यह संहिता की धारा 319 के तहत आवेदन की अनुमति देने का आधार नहीं हो सकता है। इस मामले में, विद्वान वकील ने हरियाणा राज्य बनाम राम मेहर और अन्य (2016)8 एससीसी 762 के मामले में निर्धारित कानून के सिद्धांत पर भरोसा किया है।

12. राम मेहर (सुप्रा) के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि "यह रिकॉर्ड में आया है कि बचाव पक्ष द्वारा कई वकीलों को नियुक्त किया गया था। अभियुक्तों ने अपनी पसंद के वकील को नियुक्त किया था। ऐसे में गवाहों को वापस बुलाने की स्थिति निश्चित रूप से आधार नहीं बन सकती है। यदि इसे एक आधार के रूप में स्वीकार किया जाता है, तो फिर से सुनवाई की संभावना होगी। एक अवसर हो सकता है जब इस तरह का आधार अदालत के साथ तौला जा सकता है, लेकिन निश्चित रूप से तत्काल मामला नहीं उठता इस तरह के क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए संहिता की धारा 311 के स्थापित मानदंडों के भीतर न्यायिक विवेक ।

13. साक्ष्य अधिनियम अदालत में गवाहों की परीक्षा को नियंत्रित करता है। इसका दसवां अध्याय साक्षियों के परीक्षण से संबंधित है। इस अध्याय के अंतर्गत परीक्षा, मुख्य परीक्षा और प्रतिपरीक्षा और पुन: परीक्षा का क्रम और अन्य प्रावधान दिए गए हैं। वास्तव में, ऐसे प्रावधान हैं, जो इस बात से संबंधित हैं कि गवाहों से कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रमुख प्रश्नों आदि के संबंध में भी प्रावधान हैं।

14. संहिता का अध्याय XXVIII जांच और परीक्षण में साक्ष्य से संबंधित है। संहिता की धारा 273 में प्रावधान है कि आरोपी की उपस्थिति में साक्ष्य लिया जाना चाहिए। यह इस प्रकार है:-

> "273. अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य लिया जाना.-- अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, परीक्षण या अन्य कार्यवाही के दौरान लिए गए सभी साक्ष्य अभियुक्त की उपस्थिति में लिए जाएंगे, या, जब उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी जाएगी के साथ, उनके वकील की उपस्थिति में।
>
> बशर्ते कि जहां अठारह वर्ष से कम आयु की एक महिला का साक्ष्य दर्ज किया जाना है, जिसके बारे में आरोप लगाया गया है कि वह बलात्कार या किसी अन्य यौन अपराध के अधीन है, अदालत यह सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय कर सकती है कि ऐसी महिला का सामना नहीं किया गया है। आरोपी एक ही समय में आरोपी की जिरह के अधिकार को सुनिश्चित करते हुए।
>
> स्पष्टीकरण.--इस धारा में, "आरोपी" में एक व्यक्ति शामिल है जिसके संबंध में इस संहिता के तहत अध्याय VIII के तहत कोई कार्यवाही शुरू की गई है।"

15. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता को संहिता की धारा 319 के तहत तलब किया गया है। ऐसा PW1 राकेश कुमार और PW2 संजीव पाल सिंह की परीक्षा के बाद किया गया था। संहिता की धारा 319(4) संहिता की धारा 319 के तहत अभियुक्त को समन करने के बाद की प्रक्रिया प्रदान करती है । यह इस प्रकार है।

> "319. अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की शक्ति.--
> (1) जहां, किसी अपराध की किसी जांच, या परीक्षण के दौरान, साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि कोई व्यक्ति अभियुक्त नहीं है ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है, न्यायालय ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध उस अपराध के लिए कार्यवाही कर सकता है जो उसने किया प्रतीत होता है।

(2) ……। .....
(3) .... (4) जहां न्यायालय उप-धारा (1) के तहत किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करता है तो--

> (ए) ऐसे व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी, और गवाहों को फिर से सुना जाएगा;
>
> (बी) खंड (ए) के प्रावधानों के अधीन, मामला आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा व्यक्ति एक अभियुक्त व्यक्ति था जब न्यायालय ने उस अपराध का संज्ञान लिया था जिस पर जांच या परीक्षण शुरू किया गया था।"

16. संहिता की धारा 319(4)(ए) का एक मात्र अवलोकन स्पष्ट रूप से कहता है कि संहिता की धारा 319 के तहत बुलाए गए व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही नए सिरे से शुरू की जाएगी और गवाहों को फिर से सुना जाएगा। यहां तक कि इसका शाब्दिक अर्थ भी यह स्पष्ट करता है कि जिन गवाहों का परीक्षण हो चुका है, उन्हें अभियुक्तों की उपस्थिति में उनकी परीक्षा के लिए फिर से पेश किया जाना चाहिए और इसमें मुख्य परीक्षा भी शामिल है।

17. गवाह के पिछले बयान का उपयोग कुछ उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 , एक गवाह के पिछले बयान में प्रकट हो सकने वाले विरोधाभासों के संबंध में प्रावधान करती है। जांच के दौरान एक गवाह द्वारा संहिता की धारा 161 के तहत दिए गए बयान को आसानी से संदर्भित किया

जा सकता है । अन्य स्थितियां भी हैं। संहिता की धारा 164 के तहत एक गवाह का भी परीक्षण किया जा सकता है । संहिता की धारा 164 के तहत दिए गए बयान का न केवल विरोधाभास के लिए उपयोग किया जा सकता है, बल्कि इसका उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आर. शाजी बनाम केरल राज्य , (2013)14 के मामले में पुष्टि के लिए भी किया जा सकता है। एससीसी 266।

18. संहिता की धारा 319 के तहत किसी अभियुक्त को समन करने से पहले एक गवाह की परीक्षा को नए समन किए गए आरोपी के रूप में पिछला बयान नहीं कहा जा सकता है। यहां तक कि अगर तर्क के लिए इसे पिछले बयान के रूप में कहा जाता है, तो यह केवल उसे पढ़कर गवाह की मुख्य परीक्षा नहीं बना सकता है, जब ऐसे गवाह को उसकी परीक्षा के लिए पेश किया जाता है, जो धारा 319 की धारा 319 के तहत एक अभियुक्त को बुलाया जाता है । कोड। धारा 319(4)(ए) के मद्देनजर जिन गवाहों का पहले ही परीक्षण हो चुका है उन्हें फिर से सुना जाना है।

19. शशिकांत सिंह बनाम तारकेश्वर सिंह और अन्य , (2002)5 SCC 738 के मामले में , माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से धारा 319 के प्रावधान और गवाहों की परीक्षा को निपटाया। निर्णय के पैरा 9 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संहिता की धारा 319 के तहत एक अभियुक्त को सम्मन के बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को विस्तृत किया। यह इस प्रकार है:-

> "9. यहां प्रावधान का आशय यह है कि जहां किसी अपराध की जांच, या परीक्षण के दौरान, अदालत को साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि किसी भी व्यक्ति ने अभियुक्त नहीं होने के कारण कोई अपराध किया है, अदालत हो सकती है उसके खिलाफ उस अपराध के लिए कार्यवाही करें जो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने किया है मंच, अदालत इस पर विचार करेगी कि ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है जो पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहे अदालत के समक्ष है। ऐसे व्यक्ति के संबंध में प्रदान किया गया सुरक्षा उपाय यह है कि कार्यवाही को शुरू से ही अनिवार्य रूप से नए सिरे से शुरू किया जाना चाहिए और गवाहों को फिर से सुना जाना चाहिए। संक्षेप में, उसके खिलाफ नए सिरे से मुकदमा होना चाहिए। नए सिरे से परीक्षण का प्रावधान अनिवार्य है। यह अदालत के सामने लाए गए व्यक्ति के अधिकारों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ऐसे व्यक्ति की जिरह के लिए केवल गवाहों को निविदा देना पर्याप्त नहीं होगा। इनकी नए सिरे से जांच होनी है।धारा 319(4) . ....."

20. पुनरावृत्ति की कीमत पर यह दोहराया जा सकता है कि शशिकांत सिंह (सुप्रा) के मामले में यह स्पष्ट रूप से देखा गया है, "ऐसे व्यक्ति की जिरह के लिए केवल गवाहों को निविदा देना पर्याप्त नहीं होगा, उन्हें नए सिरे से जांच की जानी चाहिए। नए जोड़े गए अभियुक्तों की जिरह के उद्देश्य के लिए नए सिरे से परीक्षा-इन-चीफ और न केवल उनकी प्रस्तुति धारा 319 (4) का जनादेश है ।

21. वर्तमान मामले में, न केवल PW2 संजीव पाल सिंह बल्कि PW1 राकेश कुमार की भी इसी तरह से संहिता की धारा 319 के तहत याचिकाकर्ता को बुलाने के बाद पूछताछ की गई थी। उन दोनों को उनकी पिछली परीक्षा-इन-चीफ के बारे में पढ़ा गया है जिसे उन्होंने अपने बयान के रूप में स्वीकार किया। लेकिन, यह कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे मुख्य परीक्षा दर्ज की जाती है।

22. दलीलों के दौरान, राज्य के विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि क्या होगा यदि कल इन गवाहों को फिर से मुख्य परीक्षा के लिए पेश किया जाए और वे एक ही भाषा बोलते हों। यह न्यायालय अनुमान नहीं लगा सकता है कि क्या होगा यदि किसी गवाह से किसी घटना के बारे में पूछा जाए और वह उसका उत्तर न दे। शायद, कानून ऐसी घटना का ध्यान रख सकता है। भारतीय दंड संहिता , 1860 के तहत प्रावधान हैं जो ऐसी स्थितियों से निपट सकते हैं।

23. वर्तमान मामले में, वास्तव में, पीडब्लू 1 राकेश कुमार और पीडब्ल्यू 2 संजीव पाल सिंह के मुख्य परीक्षा को नए सिरे से दर्ज नहीं किया गया है। पिछले बयानों को पढ़ना और उसे एक परीक्षा के रूप में लेना प्रमुख है, यह एक अनियमितता है। परीक्षण अभी तक समाप्त नहीं हुआ है।

24. निजी प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि इस न्यायालय के मुकदमे के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश दिए गए हैं और वास्तव में, जांच अधिकारी की पहले ही जांच की जा चुकी है, वर्तमान मामले में, PW1 को निविदा देने में एक अनियमितता हुई है। राकेश कुमार और पीडब्ल्यू 2 संजीव पाल सिंह को संहिता की धारा 319 के तहत याचिकाकर्ता को बुलाने के बाद उनकी परीक्षा के लिए । इस न्यायालय का विचार है कि इस स्तर पर इस अनियमितता को ठीक किया जा सकता है।

25. इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है। यह सच है कि कोड की धारा 311 के तहत आवेदन की अनुमति देने के लिए वकील का परिवर्तन एक आधार नहीं हो सकता है , लेकिन यह माना जाता है कि जब 12.03.2020 को याचिकाकर्ता की ओर से PW2 संजीव पाल सिंह से जिरह की गई थी, तो वह था जांच के दौरान दर्ज किए गए उनके पिछले बयान के बारे में नहीं पूछा गया। चूंकि यह न्यायालय संहिता की धारा 319 के तहत याचिकाकर्ता को बुलाने के बाद PW1 राकेश कुमार और PW2 संजीव पाल सिंह की जांच

करते समय हुई अनियमितता को सुधारने पर विचार कर रहा है, इसलिए यह अदालत इस पहलू को छोड़ देती है।

26. पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, इस न्यायालय का विचार है कि एक अनियमितता, जो PW1 राकेश कुमार और PW2 संजीव पाल सिंह की नई परीक्षा के दौरान की गई है, को सुधारा जाना है और तदनुसार याचिका का निपटान किया जा सकता है।

27. PW1 राकेश कुमार और PW2 संजीव पाल सिंह से नए सिरे से पूछताछ की जाएगी। उनकी मुख्य परीक्षा दर्ज की जाएगी और उसके बाद याचिकाकर्ता को उनसे जिरह करने का अवसर मिलेगा। दोनों गवाहों को एक दिन बुलाया जा सकता है और परीक्षा और जिरह दिन-प्रतिदिन के आधार पर निरंतरता में आयोजित की जाएगी। पार्टियों को इस उद्देश्य के लिए किसी भी स्थगन की मांग करने की कोई स्वतंत्रता नहीं होगी।

28. निजी प्रतिवादियों के लिए विद्वान वकील प्रस्तुत करेंगे कि 07.05.2022 मामले में तय की गई तारीख है और PW1 राकेश कुमार और PW2 संजीव पाल सिंह अपनी परीक्षा और जिरह के लिए उस तारीख को नीचे की अदालत में उपस्थित रहेंगे।

29. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि 07.05.2022 को याचिकाकर्ता PW1 राकेश कुमार और PW2 संजीव पाल सिंह दोनों से जिरह करेगा। तदनुसार, अदालत निजी प्रतिवादियों PW1 राकेश कुमार और PW2 संजीव पाल सिंह को 07.05.2022 को सुबह 10:30 बजे निचली अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश देती है। अदालत उनके बयानों को रिकॉर्ड करने के लिए आगे बढ़ेगी जैसा कि यहां पहले बताया गया है।

30. तद्नुसार याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(रवीन्द्र मैठानी, जे.) 26.04.2022 संजय